



समता ज्योति

वर्ष : 12

अंक : 6

देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र

25 जून, 2021

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in

मूल्य: प्रति अंक-5 रुपये, सालाना- 50 रुपये (चार पेज)

“जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।”

—पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को
प्रधानमंत्री के रूप
में मुख्यमंत्रियों को लिखे
पत्र से)

चाकसू विधायक की वैचारिक जड़ता बनाम समता आन्दोलन का संकल्प

जयपुर। प्रदेश में चल रही राजनैतिक उठा पटक के बीच चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने उठे पड़े चुके एस.सी/एसटी के मुद्दे को फिर से सतह पर लाने का प्रयास किया है।

विधायक के घर आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्रा पहुँचे तो उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट तुरत बनते हैं लेकिन तीन साल से दलित समाज को महिलाएँ भटक रही हैं। इसके लिये 70 विधायक सरकार

को लिखकर भी दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों से आई एस.सी/एसटी महिलाओं को राजस्थान सरकार में सर्टिफिकेट के बिना पोस्टिंग नहीं मिल रही है। सोलंकी ने साफ किया कि पार्टी हमारे लिये बड़ी है लेकिन समाज को आवाज उठाना भी जरूरी है।

वेद प्रकाश सोलंकी की प्रेस कांफ्रेंस पर एक टी वी चैनल ने शाम को ही बहस का आयोजन

किया। बहस में भाग लेते हुए समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि ये जो आरक्षित वर्ग के बाहर से आने वाले लोगों के सर्टिफिकेट बनवाने की गैर कानूनी मांग कर रहे हैं। ये जो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। सोलंकी जी जीतकर वापस नहीं आयेगी। आरक्षित वर्ग के विधायक केवल एस.सी/एसटी वोटों से नहीं बनते हैं। वेद प्रकाश सोलंकी जैसे लोगों को वापस जीतकर हम नहीं आने देंगे।

तीन भर्तियों में खाली रहे सहरिया वर्ग पदों को सामान्य से क्यों नहीं भरा : हाईकोर्ट

जयपुर, समाचार जगत न्यूज। पशुधन सहायक की वर्ष 2013, 2016 एवं 2018 की लगातार तीन भर्तियों में सहरिया वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने के बावजूद उपरोक्त पदों को सामान्य वर्ग से नहीं भरे जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। खेम चंद शर्मा की ओर से एडवोकेट आरपी सीनी ने हाईकोर्ट को बताया

कि पशुधन सहायक भर्ती-2018 में सहरिया वर्ग के लिए 21 पद आरक्षित रखे गए थे, लेकिन इस वर्ग के अभ्यर्थी ही उपलब्ध नहीं हैं। इससे पूर्व वर्ष 2016 और वर्ष 2013 में निकाली गई पशुधन सहायक भर्ती में भी सहरिया वर्ग के लिए आरक्षित पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। नियमानुसार लगातार तीन भर्तियों में आरक्षित वर्ग के पदों के लिए संबंधित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन पदों को सामान्य वर्ग से भरा जाता है।

अध्यक्ष की कलम से
अब खण्डन का मण्डन



प्रिय साधियों,

किसी एक विषय को लेकर आगे बढ़ने से मन में ऊब और थकावट का भाव आ सकता है। लेकिन कई बार विषय इतने बड़े होते हैं कि मन को थकावट के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता है। ऐसा एक विषय था 1857 में शुरू हुआ भारत का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा है देश को जाति आरक्षण से मुक्त करवाना। आजादी पाने में 90 साल लगे तो आरक्षण को समाप्त नहीं तो अप्रासंगिक बनाने के लिए 13-14 साल खर्च होना अधिक बड़ी बात नहीं है।

विशेषकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने जिस उत्साह और निष्ठा के साथ समता आन्दोलन को सहयोग दिया, वह अवश्य ही इतिहास का सुनहरा पन्ना है। इसका सुपरिणाम हजारों साधियों को प्रमोशन के रूप में मिला भी है। बावजूद इसके हमारे अनेक साधियों का मन उतना उत्साहित न दिखता जितना हुआ करता था।

जाति आधारित आरक्षण का संघर्ष कोरोना काल में स्थित हो आ लेकिन रुका नहीं। रुक सकता भी नहीं है क्योंकि ये स्वास्थ और दुःप्रह के विरुद्ध संवैधानिक श्रुति का स्थापित करने का संघर्ष है। इसलिए साधियों मन-मानस को खण्डित नहीं होने दें। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए हम देर से जागे हैं लेकिन, अभी फिर से सोने का समय नहीं आया है। हमसे हमारे बालकों के भविष्य के मण्डन की पुनः आवश्यकता है।

समता आन्दोलन का प्रत्येक सदस्य भारत राष्ट्र का समर्थित सिपाही है। समय फिर से बदल रहा है। इसके बाद हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। आइये कोरोना से खण्डित हुये मनोबल का मण्डन फिर से करें। जय समता।

पूरे देश में दस लाख पूजा स्थलों को योग स्वास्थ्य केन्द्र में विकसित किया जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पूरे देश में दस लाख पूजा स्थलों को योग स्वास्थ्य केन्द्र में विकसित किया जाये जो सरकारी/ निजी चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या 80 प्रतिशत तक कम की जा सकती है।

पत्र में निवेदन किया गया है कि 21 जून को आप श्रीमान के प्रयासों से ही विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित करवाने में सफलता मिल पाई है। यह योग दिवस करोड़ों भारतीय नागरिकों को स्वस्थ, सक्रिय एवं दक्ष रखने में हमेशा के लिए सफल हो सके इसके लिए इसे संस्थागत रूप देकर व्यापक आधार दिया जाना अति आवश्यक है।

हमारी जानकारी में गुगल सर्च में यह आया है कि पूरे भारत वर्ष में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 3.01 मिलियन अर्थात् 30 लाख 10 हजार पूजा स्थल हैं। जिनमें मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि शामिल है। हमारा आपसे आग्रह है कि उपरोक्त 30 लाख 10 हजार पूजा स्थलों में से लगभग 10 लाख पूजा स्थलों को “योग स्वास्थ्य केन्द्रों” के रूप में

सरकारी-निजी भागीदारी में विकसित किया जाए।

हमारे देश में लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है जिसमें से प्रथम चरण में 100 करोड़ जनसंख्या को लक्षित किया जावे तो उपरोक्त 10 लाख पूजा स्थलों में से औसतन प्रत्येक के कार्यक्षेत्र में लगभग 1000 जनसंख्या अर्थात् औसतन 200 परिवार आयेंगे। इन स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित और संचालित करने में निम्न बिन्दुओं पर कार्य किया जायें:-

1. प्रत्येक योग स्वास्थ्य केन्द्र पर दो प्रशिक्षित योग-स्वास्थ्यकर्मियों नियुक्त किये जाएं जिनमें उस पूजा स्थल के योग्य एवं प्रशिक्षित पूजारी, मौलवी, पादरी, ग्रंथी आदि भी शामिल हो सकते हैं।
2. उक्त योग स्वास्थ्य कर्मियों को उस क्षेत्र में आने वाले परिवारों (लगभग 200) के स्वास्थ्य की प्राथमिक जिम्मेदारी दी जाए। जिन्हें ये लगातार सुबह और शाम दो-दो घण्टे योग एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ करवाते रहें।
3. इन योग स्वास्थ्य कर्मियों को स्वस्थ, सक्रिय एवं दक्ष जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत योगासनो एवं प्राणायामों की

प्रशिक्षण देकर तैयार किया जावे और रोग विशेष के लिए आवश्यक एवं प्रभावी योग/प्राणायाम की जानकारी भी दी जावे। यह प्रशिक्षण बड़ी आसानी से तीन माह की अवधि में दिया जा सकता है। जिसके उपरान्त कठिन परीक्षा के जरिये उचित एवं मान्य प्रमाण पत्र भी दिया जाना अनिवार्य होना चाहिये।

4. इन योग स्वास्थ्य कर्मियों को बुखार, जुकाम, खांसी, नजला, सिरदर्द, पांव में मोच, साइटिका, गैस, अपच, कब्ज आदि छोटे-मोटे आम स्वभाव के कम से कम 100 रोगों का सटिक और प्रभावी उपचार के लिए आयुर्वेदिक/होम्योपैथी/यूनानी/अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की औपचारिक बतई जानी चाहिये ताकि इन सभी रोगों का आम नागरिक को निवास के नजदीक ही बहुत सस्ता, सुलभ और सुगम उपचार तत्काल मिल सके।
5. यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि किसी भी चिकित्सा पद्धति के सरकारी अथवा निजी चिकित्सालयों में किसी मरीज का ईलाज तभी किया जावे जब उसके क्षेत्र से संबंधित योग

स्वास्थ्यकर्मों द्वारा उसके उपरोक्त 100 रोगों में से किसी रोग के निदान या उपचार में अपनी असमर्थता जतते हुये उस रोगी को सदर्भित (रेफर) किया गया हो।

6. इन योग स्वास्थ्य कर्मियों को उपकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक दिये जाने हेतु उस क्षेत्र के औसतन 200 परिवारों से प्रति परिवार, प्रति माह 100 रुपये सहयोग राशि उनके पानी के बिलों में ही जोड़ कर ली जानी चाहिये। इस प्रकार एकत्र हुई राशि रुपये 20 हजार में 20 हजार का अतिरिक्त योगदान राज्य केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये। इस 40 हजार की राशि में से 15-15 हजार की राशि दोनों स्वास्थ्य कर्मियों को तथा 10 हजार की राशि उस योग स्वास्थ्य केन्द्र के सुसंचालन के लिए दी जानी चाहिये।
7. उपरोक्त योग स्वास्थ्य केन्द्रों पर संबंधित जिले अथवा तहसील मुख्यालयों पर कार्यरत आयुर्वेद/दाचार्यों, योगाचार्यों, होम्योपैथी डाक्टर, यूनानी चिकित्सक आदि की साप्ताहिक विजिट अनिवार्य की जानी चाहिये। उपरोक्त बिन्दु केवल मात्र प्रारंभिक

तौर पर दिये गये हैं। इसी प्रकार के अन्य बिन्दु संबंधित राज्य/केन्द्र सरकारों द्वारा इन योग स्वास्थ्य केन्द्रों के सुसंचालन के लिए जोड़े जा सकते हैं। इन योग स्वास्थ्य केन्द्रों से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रतिष्ठा बढ़ेगी, योग/प्राणायाम को संस्थागत रूप मिलेगा, केन्द्र/राज्यों की सरकार पर आम जनता की स्वास्थ्य समस्याओं को बोझ घटेगा, सरकारी-निजी भागीदारी होने से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन योग स्वास्थ्य केन्द्रों की उपयोगिता बढ़ेगी, ऐलोपैथी के सरकारी अथवा निजी चिकित्सालयों में मरीजों का असहनीय बोझ 80-90 प्रतिशत तक घट सकेगा, आम नागरिकों को प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, करोड़ों भारतवासियों को स्वस्थ-सक्रिय-दक्ष जीवन का आनन्द मिल सकेगा, चिकित्सा क्षेत्र के भ्रष्टाचार की रोकथाम होगी, आम नागरिक अपने सहज-सुलभ-सुगम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकेगा।

पत्र की प्रति सभी सम्माननीय राज्यसभा व लोकसभा सांसदों को भी भेजी गई है।

सम्पादकीय

“समस्या में ही समाधान”

देश

करवट ले रहा है। सच में जाति आरक्षण के मामले में देश कुछ बढ़ा और सही निर्णय लेने की तरफ बढ़ रहा है। नहीं। हम यहाँ कथित राजनेताओं को प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं। वे तो सभी अपने निजि और पार्टी स्वार्थ के चलते फेल हो चुके हैं। यदि देश में सक्रिय पार्टियाँ और नेता देश के बारे में चिंतन रखते होते तो जाति आरक्षण का भस्मासुर खड़ा ही नहीं होता।

भस्मासुर पौराणिक काल का ऐसा चरित्र था जो जिसके सिर पर हाथ रखता था वह वहाँ भस्म होकर समाप्त हो जाता था। अन्ततः परिस्थितियाँ ऐसी बनी या बनाई गयी कि उसने प्रमाद में अपने ही सिर पर हाथ रखा और स्वयम् नष्ट हो गया। यहाँ लोकतंत्र का यह सिद्धान्त प्रमाणित होता है कि “प्रत्येक समस्या का समाधान स्वयम् समस्या में ही छुपा होता है” – इसीलिए जटिल समस्याओं को तत्काल सुलझाने के बजाय उसे ढीला छोड़ दिया जाता है। धारा 370, गोरखा लैंड, भाषा आदि अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जो समय लेकर सुलझ गये।

असल में जाति आरक्षण कोई समस्या नहीं थी। यह कथित राजनेताओं का स्वार्थ है जिसने सामाजिक समरसता का विकल्प कथित राजनीति में दूँडने का प्रयास किया और देश की विकास प्रक्रिया को बाधित किया। यह कोई आरोप नहीं वरन् तथ्य है। बड़ी अदालतों ने अपने निर्णयों में बार-बार इसे प्रमाणित भी किया है।

हाँ, तो फिर से लौटते हैं “समस्या में छुपे समाधान” पर। यहाँ यह तथ्य उजागर करना जरूरी है कि यदि 2008 में समता आन्दोलन का उदय नहीं होता तो जाति आरक्षण देश को पूरी तरह बर्बाद कर चुका होता। इस आन्दोलन ने जाति आरक्षण की समस्या को सामाजिक बुराई और राजनैतिक चतुराई से बाहर निकालकर संवैधानिक शुचिता का विषय बनाया। इसका परिणाम हुआ कि देश की संसद को ई डब्ल्यू एस आरक्षण को लागू करना पड़ा।

दूसरी तरफ सरकारों ने सरकारी नौकरियों को कुल संख्या के आधे तक घटाकर जाति आरक्षण की शक्ति को अत्यन्त क्षीण बना दिया। तीसरी बात निजी क्षेत्र में परोक्ष आरक्षण नीति तो लागू की लेकिन प्रत्यक्षतः कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर भारत देश जाति आरक्षण के अभिशाप से मुक्त होने को है।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

समता क्रिज कान्टेस्ट उत्तर

1 (C)	11 (D)	21 (D)	31 (B)	41 (C)
2 (C)	12 (B)	22 (C)	32 (B)	42 (D)
3 (C)	13 (D)	23 (A)	33 (D)	43 (D)
4 (D)	14 (A)	24 (D)	34 (D)	44 (C)
5 (B)	15 (D)	25 (B)	35 (D)	45 (C)
6 (A)	16 (D)	26 (C)	36 (D)	46 (D)
7 (D)	17 (D)	27 (D)	37 (C)	47 (B)
8 (B)	18 (B)	28 (C)	38 (B)	48 (C)
9 (B)	19 (B)	29 (C)	39 (D)	49 (C)
10 (C)	20 (D)	30 (A)	40 (C)	50 (D)

उत्साहजनक रहा समता क्रिज कान्टेस्ट, 2021

दिनांक: 23 मई 2021, रविवार को सांय 4.00 बजे ऑन लाइन आयोजित

समता क्रिज कान्टेस्ट की प्रश्नोत्तरी

1 समता आन्दोलन का स्थापना दिवस बताएँ:-

- (a) 9 मई, 2008 (b) 10 मई, 2008
(c) 11 मई, 2008 (d) 11 मई, 2009

2 समता आन्दोलन के मासिक समाचार पत्र का नाम:-

- (a) समता प्रकाश (b) समता ज्ञान
(c) समता ज्योति (d) समता दर्शन

3 समता आन्दोलन की वेबसाइट का लिंक कौन सा सही है:

- (a) www.samtaandolan.com.in
(b) www.samtaandolan.com.in
(c) www.samtaandolan.co.in
(d) www.samtaandolan.co.in

4 समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्षों का कौनसा वाक्य सही है:-

- (a) श्री पाराशर नारायण शर्मा (राष्ट्रीय), श्री रामनिरंजन गौड़ (राजस्थान), श्री धर्मवीर चौधरी (हरियाणा), श्री दीनबन्धु सारंगी (उड़ीसा)
(b) श्री पाराशर नारायण शर्मा (राष्ट्रीय), श्री योगेन्द्र राठौड़ (राजस्थान), श्री गिरजेश शर्मा (उत्तर प्रदेश), श्री दीनबन्धु सारंगी (उड़ीसा).
(c) श्री पाराशर नारायण शर्मा (राष्ट्रीय), श्री राम निरंजनगौड़ (राजस्थान), श्री अशोक शर्मा (मध्य प्रदेश), श्री धर्मवीर चौधरी (हरियाणा).
(d) श्री पाराशर नारायण शर्मा (राष्ट्रीय), श्री पाराशर नारायण शर्मा (राजस्थान), श्री दीनबन्धु सारंगी (उड़ीसा), श्रीराम पंसारी (चड़ीगढ)

5 “जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं विध्वंसकारी है” यह वाक्य किसने किससे कहा ?

- (a) डा० भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा से।
(b) प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्य मंत्रियों से।
(c) सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पं. जवाहरलाल नेहरू से।
(d) प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोकसभा के सांसदों से।

6 समता आन्दोलन के संस्थापक सदस्यों के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है ?

- (a) श्री पाराशर नारायण शर्मा, श्री अनिल अग्रवाल, श्री मोहन लाल महेश्वरी, श्री शिवदत्त जी.
(b) श्री पाराशर नारायण शर्मा, श्री रामनिरंजन गौड़, श्री योगेन्द्र सिंह राठौड़, श्री दीपक सिंघल.
(c) श्री पाराशर नारायण शर्मा, श्री योगेश्वर शर्मा, श्री रवीन्द्र पारीक, श्री विमल चौराडिया.
(d) पाराशर नारायण शर्मा, श्री अभिशेक कौशिक, श्री नवरंगलाल सिंगडोदिया, श्री चाबुलाल विजय.

7 केन्द्र और राजस्थान में आज की तारीख में नौकरी में आरक्षण कोटे के सम्बन्ध में कौन सा वाक्य सही है ?

- (a) केन्द्र में (SC) 15%, (ST) 7.5%, (OBC) 27%, (MBC) 5%, (EWS) 10%.
(b) राजस्थान में (SC) 16%, (ST) 12%, (OBC) 27%, (MBC) 5%, (EWS) 10%.
(c) केन्द्र में (SC) 15%, (ST) 7.5%, (OBC) 21%, (MBC) 5%, (EWS) 10%.
(d) राजस्थान में (SC) 16%, (ST) 12%, (OBC) 21%, (MBC) 5%, (EWS) 10%

8 पदोन्नति में जातिगत आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य में कब से बन्द है? किस मुख्यमंत्री ने बन्द किया है ?

- (a) वर्ष-2011 से श्री अखिलेश यादव ने. (b) वर्ष-2012 से श्री अखिलेश यादव ने. (c) वर्ष-2013 से श्री अखिलेश यादव ने (d) वर्ष-2014 से श्री अखिलेश यादव ने.

9 समता आन्दोलन के लैटर हेड पर अंकित ईमेल आईडी कौन सी है ?

- (a) samtaandolan@gmail.com
(b) samtaandolan@yahoo.in
(c) samta_andolan@gmail.com
(d) samta_andolan@yahoo.in

10 हाल ही में समता आन्दोलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया ?

- (a) बारहवाँ (b) तेरहवाँ (c) चौदहवाँ (d) पन्द्रहवाँ

11 समता आन्दोलन द्वारा प्रकाशित मासिक समाचार पत्र के लिए कौन सा वाक्य सही है-

- (a) नाम-समता ज्योति, सम्पादक-पाराशर नारायण शर्मा, प्रकाशक-समता आन्दोलन प्रन्त्यास, प्रसार संख्या-10,000

(b) नाम-समता ज्योति, सम्पादक-आर० एन० गौड़, प्रकाशक. श्री पाराशर नारायण शर्मा, प्रसार संख्या-5000

(c) नाम-समता ज्योति, सम्पादक-दीपक सिंघल, प्रकाशक. श्री पाराशर नारायण शर्मा, प्रसार संख्या-10,000

(d) नाम-समता ज्योति, सम्पादक-श्री योगेश्वर शर्मा, प्रकाशक. समता आन्दोलन समिति, प्रसार संख्या-5000

12 समता आन्दोलन के उद्देश्यों और कार्यशैली को समाहित करने वाला एक पृष्ठीय अतिमहत्वपूर्ण “नीति-पत्र” समता की वेबसाइट पर कहाँ पढ़ा जा सकता है ?

- (a) होम पेज पर (b) “About us” शीर्ष में
(c) “News&Activities” शीर्ष में (d) “उद्देश्य” शीर्ष में
13 समता आन्दोलन की वेबसाइट पर जो “समता-गान” और “समता-गीत” दिये गये है इनके बारे में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है-

- (a) प्रत्येक कार्यक्रम के शुरू में समता-गान गाया जावे.
(b) प्रत्येक कार्यक्रम के अन्त में समता-गीत गाया जावे.
(c) प्रत्येक कार्यक्रम के शुरू में समता-गीत व अन्त में समता-गान गाया जावे.
(d) प्रत्येक कार्यक्रम का शुरूआत समता-गान से और समाप्ति समता-गीत से की जावे.

14 समता आन्दोलन की वेबसाइट पर जिन चार संरक्षकों के नाम अंकित है उनके बारे में कौन सा कथन सही है ?

- (a) जस्टिस पानाचंद जैन, श्री अमिताभ गुप्ता (पूर्व DGP), श्री जे. एस. राठौड़ (पूर्व त्रिगेडियर), श्री भागीरथ शर्मा (पूर्व IAS).
(b) जस्टिस पानाचंद जैन, श्री अमिताभ गुप्ता (पूर्व DGP), श्री अशोक कुमार सिंह (पूर्व मेजर जनरल), श्री भागीरथ शर्मा
(c) जस्टिस पानाचंद जैन, श्री आर.डी. गोयल (पूर्व IGP), श्री अशोक कुमार सिंह (पूर्व मेजर जनरल).
(d) जस्टिस पानाचंद जैन, श्री आर.डी. गोयल (पूर्व IGP), श्री अशोक कुमार सिंह (पूर्व मे. जनरल), श्री भागीरथ शर्मा (पूर्व IAS)

15 समता आन्दोलन की वेबसाइट के होम-पेज पर सभी सामग्री की अनुक्रमणिका बाईं ओर दी गयी है। इस अनुक्रमणिका में दिये गये सामग्री शीर्षकों के सम्बन्ध में कौन सा कथन गलत है:-

- (a) Board Members-2018, Mission-59, State Executive -2018, Tehsil Executive.
(b) Nagar Executives, Prakoshttha Executive, Members, Samta Activists.
(c) Samta Jyoti Newspaper, Court Judgements, Press Clips, Photo Gallery.
(d) Video Library, Budget Status, Receipt Book Status, Samta Andolan Rules.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

पौराणिक कथन: ‘अशोकाष्टमी’

चैत्र शुक्लाष्टमी के दिन शोक निवारण के लिए अशोक वृक्ष के आठ पत्ते पानी में डालकर पीते है और विष्णु की पूजा होती है।

देश धर्म को कहना होगा,

अधिक नहीं अब सहना होगा।

जातिवाद के बंध तोड़कर-

मुक्त गगन में रहना होगा।।

‘समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएँ’

कविता

“ गर्म हवाएँ ”

उठता ही रहता है

गर्म हवाओं का गुरूर

ऊपर भी जाता है

किंतु ठहर नहीं पाता है,

जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है

कम होने लगती है

प्राण वायु की गरमी

ठंडा होता जाता है

शून्य बनता आकाश

वहाँ नहीं मिलती

बैठकर सुस्ताने की जमीन

और बतियाने वाले हमसफर

फिर ताप का असर

जब घटने लगता है

गुरूर कटने लगता है

गर्म हवाएं लौटना चाहती हैं

लौट नहीं पाती हैं

गुरूर काल्पनिक हो कि संवैधानिक

ऊपर जाता तो दिखता है

लौटता हुआ नहीं

कभी भी नहीं

बड़े लोग कह गये हैं

बहुत ऊपर जाना

और ठंडा होना एक ही बात है

लेकिन वापस न आ पाना

दूसरी बात

बेहतर होती है हमेशा

तीसरी बात

न गर्म गुबार बनो

न शीत हवाएँ

जीवन बसता है

फलता-फूलता है

बासंती बयार में

जब समझ जाओगे

तब निजको पाओगे।

- समता डेस्क -

(पृष्ठ 2 का शेष)

16. समता आन्दोलन के लोगो (Logo) पर अंकित शब्द युग्मों के सम्बन्ध में कौन सा कथन असत्य है-

- (a) सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर-इन्सान-एक समान, जातिगत आरक्षण बन्द करो
(b) सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर-इन्सान-एक समान, जातिगत आरक्षण अभिशाप है।
(c) सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर-इन्सान-एक समान, एक राष्ट्र एक जान।
(d) सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर-इन्सान-एक समान, समता आन्दोलन।

17. समता आन्दोलन की वेबसाइट के Home Page पर ही समता आन्दोलन के चार उद्देश्य दिये गये हैं, इन उद्देश्यों के सम्बन्ध में कौन सा कथन असत्य है:-

- (a) हर इन्सान-एक समान, जातिगत आरक्षण बन्द हो, एक राष्ट्र एक जान, मेरा भारत महान.
(b) हर इन्सान-एक समान, जातिगत आरक्षण अभिशाप है, एक राष्ट्र एक जान, मेरा भारत महान.
(c) हर इन्सान-एक समान, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, एक राष्ट्र एक जान, मेरा भारत महान.
(d) हर इन्सान-एक समान, एक राष्ट्र एक जान, मेरा भारत महान, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेभन्तु निरापन्ना.....

18. समता आन्दोलन वेबसाइट के "News & Activities" शीर्षक मे समता आन्दोलन की चुनी हुई गतिविधियों और जरूरी खबरों को अपलोड किया जाता है। आज तारीख में इस शीर्षक में अपलोड की गई गतिविधियों और जरूरी खबरों की संख्या के सम्बन्ध में कौन सा उतर निकटतम रूप से सही है:-

- (a) 350 से अधिक (b) 370 से अधिक
(c) 400 से अधिक (d) 420 से अधिक

19. संसद द्वारा पारित और 15.08.2018 से अधिसूचित 102 वें संविधान संशोधन की खास बातों में कौनसा कथन असत्य है:-

- (a) National Commission For Backward Classes को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
(b) OBC की परिभाषा केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा तय की जायेगी।
(c) अब NCBC द्वारा अनुमोदित, संसद के बिल द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जाति/वर्ग/समुदाय ही OBC होंगे।
(d) दिनांक 15.08.2018 तक केन्द्र एवं राज्यों में जारी सभी OBC सूचियाँ असंवैधानिक हो गयीं हैं।

20. OBC आरक्षण से संबंधित 102 वें संविधान संशोधन के बाद OBC की अधिसूचनाएँ राष्ट्रपति से जारी करवाने के लिए समता आंदोलन द्वारा जो प्रयास किये गये है उनसे असंगत वाक्य कौनसा है?

- (a) समता अध्यक्ष द्वारा यूट्यूब पर एक वीडियो जारी की गयी जिस सात लाख से अधिक लोगों ने देखा, जनजागरण के जरिये याचिकाएँ लगाने की अपील।
(b) मंडिकल प्रवेश परीक्षा और केन्द्र/राज्य की भर्तियों से संबंधित पत्रियों/सचिवों व विभागाध्यक्षों को ज्ञापन दिये गये।
(c) राजस्थान उच्च न्यायालय में 2 एवं सर्वोच्च न्यायालय में 1 याचिका दायर की गयीं हैं।
(d) जयपुर और दिल्ली में अप्रैल 2019 में सांकेतिक धरने आयोजित किये

21. दिनांक 15.08.2018 से पूरे देश में प्रवृत्त 102 वें संविधान संशोधन के प्रभाव से संबंधित कौनसा कथन असत्य है:-

- (a) राज्यों को अब OBC घोषित करने या OBC की सूची जारी करने या उसमें संशोधन का कोई अधिकार नहीं रहा है।
(b) दिनांक 15.08.2018 से पहले या बाद में राज्यों द्वारा जारी सभी OBC की सूचियाँ अवैध एवं असंवैधानिक हो गयीं हैं।
(c) वास्तविक पिछड़े एवं वंचितों तक लाभ पहुंच जायेगा। सम्पन्न जाति/व्यक्ति बाहर होंगे।
(d) केन्द्र एवं राज्यों में जातिवाद बहेगा।

22. दिनांक 15.08.2018 से पूरे देश में प्रवृत्त 102 वें संविधान संशोधन के प्रभाव से संबंधित कौनसा कथन असत्य है:-

- (a) आज की तारीख में पूरे देश में संवैधानिक रूप से कोई OBC विद्यमान नहीं है।
(b) आज की तारीख में व्यवहारिक और संवैधानिक दृष्टि से केन्द्र में केवल 32.5% (15% SC + 7.5% ST + 10% EWS) और राजस्थान में केवल 38% (16% SC + 12% ST + 10% EWS) आरक्षण चालू है।
(c) राज्यों की सरकारों पर जातिगत समुदायों के आन्दोलनों का दबाव बहेगा।
(d) राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचनाएँ जारी होने पर OBC आरक्षण पुनः नये मानदण्डों पर चालू होगा।

23. दिनांक 25.07.2019 को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री गुजरात, सभी सांसदों, गुजरात व राजस्थान के सभी विधायकों को भेजे गये महत्वपूर्ण ज्ञापन के संबंध में कौनसा कथन असत्य है ?

- (a) EWS का आधार केवल आय की सीमा हो, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 5 मानदण्ड हटाए जाये।
(b) OBC का आधार जाति से हटाकर व्यवसाय जैसे खेती, बर्हई, लुहारी, कुम्हारी आदि को बना दिया जावे।

(c) गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री और राजस्थान के विधायक श्री कालीचरण सराफको निर्देशित किया जावे।
(d) EWS के पांचों मानदण्ड OBC पर भी लागू किये जावें।

24. EWS के पांचों मानदण्डों के बारे कौनसा कथन असत्य है ?

- (a) ये पांचों मानदण्ड किसी भी जातिवर्गों में वास्तविक पिछड़े व वंचित की पहचान करने में सक्षम है।
(b) समता आन्दोलन EWS के पांचों मानदण्डों को OBC में भी लागू करवाना चाहता है जिससे जातिवाद खत्म हो।
(c) इन मानदण्डों के लागू होने पर आरक्षण का गलत लाभ लेने वालों की पहचान आसानी से हो सकेगी।
(d) उपरोक्त कारणों से ही राजस्थान सरकार ने भी EWS के पांचों मानदण्ड यथावत रखे है।

25. 102 वें संविधान संशोधन के बाद वर्ष 2019 एवं 2020 में राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण नहीं दिये जाने के लिए समता आन्दोलन द्वारा कौनसा प्रयास नहीं किया गया।

- (a) श्रीमान मुख्य सचिव एवं मुख्य चुनाव आयुक्त (राज.) को ज्ञापन
(b) श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से समता आन्दोलन का शिटमंडल मिला।
(c) श्रीमान राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया।
(d) राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।

26. समता अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में से क्रीमिलेयर को बाहर करवाने के लिए कौनसा प्रयास नहीं किया गया।

- (a) सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
(b) सर्वोच्च न्यायालय को संविधान पीठ द्वारा जर्नेल सिंह के प्रकरण में 26.09.2018 को दिये गये निर्णय के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन दिये गये।
(c) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से शिट मंडल मिला है।
(d) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सभी सांसदों को ज्ञापन भेजे गये।

27. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के लिए कौनसा मानदंड शामिल नहीं है।

- (a) अस्पृश्यता
(b) सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ापन
(c) सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ापन अस्पृश्यता को पारम्परिक प्रथा के कारण
(d) अनुसूचित जाति की सूची में उस जाति का नाम शामिल हों।

28. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए कौनसा मानदंड शामिल नहीं है।

- (a) आदिम प्रवृत्तियों के संकेत और विशिष्ट संस्कृति
(b) भौगोलिक अलगाव और पिछड़ापन
(c) अस्पृश्यता
(d) समुदाय के साथ सम्पर्क करने में संकोच।

29. सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद SC/ST के लोग उनके लिए नियमानुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को अनुच्छेद 15 एवं 16 में आरक्षण का लाभ बंद करने के लिए समता आन्दोलन द्वारा किये गये प्रयासों के संबंध में असत्य कथन कौनसा है ?

- (a) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ज्ञापन दिया गया।
(b) CJI को ज्ञापन दिया गया।
(c) राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
(d) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी सांसदों को ज्ञापन दिया गया।

30. समता अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के बारे में कौनसा कथन असत्य है

- (a) यह प्रकोष्ठ जातिगत आरक्षण का पक्षधर नहीं है।
(b) यह प्रकोष्ठ पदोन्नति में आरक्षण का पक्षधर नहीं है।
(c) यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जातिवर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करवाना चाहता है।
(d) इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री राकेश वर्मा हैं।

31. समता अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के बारे में कौनसा कथन असत्य है ?

- (a) यह प्रकोष्ठ मीणा समुदाय को ST से बाहर करवाने को प्रयासरत है।
(b) यह प्रकोष्ठ मीणा समुदाय को ST से बाहर करने को याचिका लगा चुका है
(c) यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जनजाति वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करवाना चाहता है
(d) यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जनजाति के NON-TSP जनजाति लोगों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रहा है।

32. वर्ष 2019 में राजनैतिक आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाने वाले संविधान संशोधन को रूकवाने के लिए समता आन्दोलन ने जो कदम उठाये है उनमें से कौनसा कथन असत्य है ?

- (a) संविधान संशोधन बिल पारित करवाने हेतु पार्टी विप जाओ करने से रूकवाने के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिये गये।
(b) दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाई।
(c) लोकसभा अध्यक्ष से समता के 11 सदस्य शिट मंडल ने मिलकर उनसे संविधान पीठ द्वारा किहोटी हॉलीवुड प्रकरण में दिये गये निर्णय की पालना का आग्रह किया गया।
(d) सभी सांसदों को ज्ञापन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना का आग्रह किया गया।

(पृष्ठ 3 का शेष)

33. समता आन्दोलन समस्या के जड़ों पर चर्चा करने वाला संगठन है। सांसदों और विधायकों द्वारा अर्सेवैधानिक कृत्व करने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए समता आन्दोलन द्वारा किये गये प्रयासों में कौनसा असत्य है ?

- संविधान की शपथ का उल्लंघन करने वाले विधायकों/सांसदों की सदस्यता रद्द करने/उन्हें दंडित करने के प्रावधान अनुच्छेद 191 व लोक प्रविधिध्व कानून 1951 में जोड़ने के ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानूनमंत्री को दिये।
 - पंजाब व राजस्थान में शपथ का उल्लंघन करने वाले विधायकों को सदस्यता रद्द करने की याचिका अनुच्छेद 192 के अधीन राज्यपालों को पेश।
 - पश्चिम बंगाल व केरल में शपथ का उल्लंघन करने वाले विधायकों को सदस्यता रद्द करने की याचिका अनुच्छेद 192 के अधीन राज्यपालों को पेश।
 - संसद में शपथ का उल्लंघन करने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द करने की याचिका अनुच्छेद 192 के अधीन राष्ट्रपति को पेश।
34. देश में प्रजातंत्र के रक्षार्थ बिखरे और दिशाहीन विपक्ष को मजबूत करने के लिए समता आन्दोलन द्वारा श्री राहुल गांधी व श्रीमती सोनिया गांधी सहित कांग्रेस-टीएमपी के सांसदों को दिनांक 20.02.2020 को भेजे ज्ञापन में कौनसा सुझाव नहीं दिया गया।

- कांग्रेस में टीएमपी को समाहित करके सुश्री ममता बनर्जी को अध्यक्ष बनाया जाये।
- श्री अशोक गहलोट को कांग्रेस का सर्व शक्ति सम्पन्न राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाये।
- श्री राहुल गांधी एवं श्रीमती प्रियंका गांधी को अनुभवी और ज्ञानवान भारतीय राजनेता बनने के लिए अभी सघन प्रशिक्षण की जरूरत है।
- कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव वधायीय करवाया जाये।

35. जब तक जातिगत आरक्षण समाप्त नहीं होता तब तक आरक्षण का रोस्टर पारदर्शी होने पर ही आरक्षण प्रावधानों की सही पालना हो सकती है। नियुक्तियों व पदोन्नतियों में आरक्षण रोस्टर पारदर्शी बनवाने के लिए समता आन्दोलन द्वारा राजस्थान में कौनसा प्रयास नहीं किया गया है।

- दिनांक 20.03.2020 को मुख्य सचिव से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया।
- उक्त ज्ञापन में डीओपी के 24 फरवरी 2020 के आदेश द्वारा रोस्टर अनिवार्य करने के लिए साधुवाद दिया गया।
- रोस्टर को ऑनलाईन करने, पदोन्नति व नियुक्ति में आरक्षण से पहले रिक्त रोस्टर बिन्दुओं की विज्ञप्ति अनिवार्य करने और प्रष्ट डीओपी, डीएस श्री जयसिंह को दंडित करने की मांग की गई।
- मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल के जरिये उक्त ज्ञापन पर कार्यवाही की मांग।

36. सरकारी नौकरी प्राप्त SC,ST कर्मचारियों के लिए समता आन्दोलन की सोच को कौनसा वाक्य स्पष्ट करता है ?

- उन्हे या उनके बच्चों को अनुच्छेद 15 व 16 का लाभ नहीं मिलना चाहिये।
- चूँकि वे केन्द्र सरकार द्वारा SC,ST के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते अतः उन्हें सामान्य नागरिकवर्ग में प्रतियोगिता देना चाहिये।
- सरकारी नौकरी प्राप्त SC,STको सामान्य नागरिक मानने से इसी वर्ग के वरिष्ठों को लाभ होगा, जातिवाद खत्म होगा अनावश्यक लिटिगेशन खत्म होगा, लोक सेवकों को दक्षता बढेगी।
- उपरोक्त सभी।

37. संविधान संशोधन के समय संसद में पार्टी विधि जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस संविधान संशोधन के मुद्दे पर जनआदेश नहीं लिया गया हो। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के किस निर्णय में प्रतिपादित किया गया ?

- एम नागराज एवं अन्य बनाम भारत सरकार - 2006
- इन्दिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार - 1992
- किहोटी होलोहॉन बनाम जच्चिहू एवं अन्य - 1992
- जरनेल सिंघ एवं अन्य बनाम भारत सरकार - 2018

38. जनवरी-1920 में समता आन्दोलन द्वारा चार राज्य के राज्यपालों को वहाँ के कुछ विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए अनुच्छेद-192 के अधीन याचिका पेश की गयी थी। इन याचिकाओं का विषय क्या था ?

- पदोन्नति में आरक्षण विषय पर बिल पारित करके शपथ का उल्लंघन
- CAA-2019 कानून के विरुद्ध बिल पारित करके शपथ का उल्लंघन
- पंचायत चुनावों में आरक्षण का बिल पारित करके शपथ का उल्लंघन
- एट्रोसिटी एक्ट पर बिल पारित करके शपथ का उल्लंघन

39. राजनैतिक आरक्षण समाप्त करवाने के लिए समता आन्दोलन द्वारा वर्ष 2009 में जनहित याचिका लगाई गयी थी जो लम्बित हैं। इस याचिका में लिये गये कुछ आधारों को शामिल करते हुए दिसम्बर 2019 में लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया, इन्हीं आधारों को नीचे दिया गया है। यह बताये कि कौनसे आधार सही हैं ?

- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आठ याचिकाएँ लम्बित है।
- आरक्षित सीटों पर करोड़ों नागरिकों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करना अर्सेवैधानिक है, लोकतंत्र का मजाक है।
- सांसदों को विधि जारी करके अपने विवेकानुसार मतदान करने से रोकना अर्सेवैधानिक है, वाक एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन है।
- राजनैतिक आरक्षण बढ़ते वक्त संविधान संशोधन हेतु विधि जारी करना सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के किहोटी होलोहॉन प्रकरण निर्णय का उल्लंघन है।
- राजनैतिक आरक्षण बढ़ाने के संविधान संशोधन के पक्ष में सांसदों द्वारा मतदान करना अपने मतदाताओं से विद्यासप्त है, शपथ का उल्लंघन है।

- अनुच्छेद- 334 में राजनैतिक आरक्षण की व्यवस्था करते वक्त संविधान निर्मात्री सभा ने सर्वसम्मति से तय किया था कि यह आरक्षण दस वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो जायेगा। कोई समीक्षा या पुनर्विचार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इसे 10-10 वर्ष बढ़ाना अर्सेवैधानिक है, मूलभूत संरचना का उल्लंघन है, स्वतंत्रता सैनानियों का अपमान है।
- अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है।

विकल्प:-

- उपरोक्त में (a) से (f) तक सही
- उपरोक्त में (a)से (e)तक सही
- उपरोक्त में (a) से (d) तक सही
- उपरोक्त में सभी (a) से (g) तक सही

40. राजस्थान में आरक्षण प्रावधानों की अक्षरशः पालना हेतु प्रत्येक विभाग की रोस्टर पत्रिका को ONLINE करने के लिए समता आन्दोलन द्वारा मुख्य सचिव को मार्च-2020 में ज्ञापन दिया गया था। इस सम्बन्ध में कौनसा कथन असत्य है ?

- तत्कालीन मुख्य सचिव ने हमारे ज्ञापन पर ही आदेश कर दिये थे।
- DOP द्वारा भी आदेश जारी कर दिये गये हैं।
- सभी विभागों की रोस्टर पत्रिकाएँ ONLINE हो चुकी हैं।
- रोस्टर पत्रिकाएँ संधारित किये बिना पदोन्नति व नियुक्तियों में आरक्षण अर्सेवैधानिक है।

41. श्री गुलाब कोठारी, प्रधान सम्पादक, राजस्थान पत्रिका द्वारा दिनांक 28.04.2020 को आरक्षण पर एक अग्रलेख लिखा गया था। इसके सम्बन्ध में कौन सा वाक्य असत्य है ?

- इस अग्रलेख का शीर्षक "पुनर्विचार आवश्यक" था।
- यह राजस्थान पत्रिका के प्रथम/मुख्यपृष्ठ पर प्रकाशित था।
- इस अग्रलेख को पढकर SC/ST का क्रॉमिलेयर वर्ग सहम गया था।
- इस अग्रलेख पर SC/ST के क्रॉमिलेयर वर्ग के द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए गये नकारात्मक अभियान का समता आन्दोलन ने मुहूर्तोड़ जवाब दिया, उन्हें धूल चटाई।

42. समता अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में क्रॉमिलेयर को बाहर करवाने के लिए याचिका सं. 2/2018 दायर की हुई है। इसके सम्बन्ध में कौनसा कथन असत्य है ?

- CJI को जल्दी निर्णय करने के लिए मई-2018 में ज्ञापन दिया गया।
- जल्दी निर्णय/सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन पेश किये
- SC/ST से क्रॉमिलेयर बाहर करने के लिए अधिसूचना जारी करने का ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया गया।
- इस याचिका का शीर्ष निर्णय करवाने के लिए राष्ट्रपति एवं चार कांटेसिल को ज्ञापन दिये गये।

43. कोरोना काल में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए समता आन्दोलन द्वारा अनेक प्रयास किये गये। कौनसा कथन असत्य है ?

- आयुर्वेद को प्रमुखा देने के लिए किसी प्रखर राजनेता को आयुषमंत्री बनाने की मांग का प्रधानमंत्री को दिनांक 09.05.2020 को ज्ञापन दिया गया।
- समता आन्दोलन के आयुर्वेद प्रकोष्ठ का पुनर्गठन करके उसे सशक्त, क्रियाशील करने का प्रयास किया गया।
- राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सकों को एलोपैथी PMO के अधीन लगाने के आदेश को वापिस लेने के लिए आयुर्वेद सचिव श्रीमती गायत्री राठी, को पत्र लिखा गया।
- कोरोना पीजीटीव के 50 मरीज समता आयुर्वेद प्रकोष्ठ को आयुर्वेदिक इलाज के लिए सीपने का पत्र राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया।

44. भारतीय प्रजातंत्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए समता आन्दोलन द्वारा मई, 2020 में मुख्य चुनाव आयुक्त को किन्हीं कारणों से मतदान स्थल तक नहीं पहुँच पाने वाले मतदाताओं को ऑनलाईन मतदान का विकल्प देने हेतु ज्ञापन दिया गया था। इस ऑनलाईन मतदान के प्रभावों के बारे में कौन सा वाक्य असत्य है ?

- किन्हीं कारणों से (शहर से बाहर होना,अशक्त होना आदि)मतदान स्थल तक नहीं पहुँच पाने वाले मतदाताओं को प्रजातंत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
 - मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, भारतीय प्रजातंत्र और अधिक मजबूत, पारदर्शी व सशक्त होगा।
 - गुणधर्मों व फर्जों मतदान पूर्णतः बन्द हो जायेगा।
 - अनिवार्य मतदान कानून लाने का रास्ता साफ होगा।
45. राजस्थान में कोरोना उपचार हेतु आयुर्वेद विभाग को सशक्त और सक्रिय बनाने के लिए समता आन्दोलन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कौन सा कथन असत्य है ?
- किसी क्षमतावान एवं विवेकशील आईएएस को आयुर्वेद सचिव बनाने की मांग का ज्ञापन जून, 2020 में मुख्य सचिव को।
 - किसी क्षमतावान एवं विवेकशील आईएएस को आयुर्वेद सचिव बनाने की मांग का ज्ञापन जून, 2020 में स्वास्थ्य मंत्री को।
 - आयुर्वेद का पृथक मंत्रालय एवं मंत्री बनाने की मांग का ज्ञापन जून, 2020 में मुख्यमंत्री को।

- कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप का मुकाबला करने के लिए आयुर्वेदाचार्यों को सेवाएँ लेने, जिला स्तर पर 100-100 बेड वाले आयुष कोविड औषधालय चालू करने की मांग का ज्ञापन, जून 2020 में स्वास्थ्य मंत्री जी को।

46. मार्च, 2020 में समताआन्दोलन द्वारा राजस्थान में DOP उपशासन सचिव श्री जयसिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 167 एवं 120 जी के अधीन प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति के लिए मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया था। इस ज्ञापन में शामिल आधारों के सम्बन्ध में कौनसा कथन असत्य है ?

- श्री जयसिंह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है,सामान्य / ओबीसी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है।
- श्री जयसिंह द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.11.1997, 11.09.2011 एवं 26.07.2017 की जानबूझ कर अवहेलना करके सामान्य एवं ओबीसी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति की जा रही है।
- श्रीजयसिंह द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4) का उल्लंघन करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु सामान्य एवं ओबीसी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है।
- श्रीजयसिंह द्वारा एससी, एसटी के कामियों से मिलीभगत करके सम्बन्धित पत्रावलियों में हेरफेर किया जा रहा है, सामान्य एवं ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, स्वयं की स्वार्थ पूर्ति की जा रही है।

47. यह सर्वविध है कि पूरे भारत वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनैप कुमार के प्रकरण में दिये गये निर्णय के बाद 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में सामान्यतय गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। राजस्थान में श्री रविप्रकाश मेहरडा (एससी), एट्रोसी सिविल राइट्स ने दिनांक 29.05.2020 को एक अतिरिक्त परिपत्र जारी करके एट्रोसिटी के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने ही गिरफ्तारी को अनिवार्य बना दिया। इस सम्बन्ध में समता आन्दोलन द्वारा किये गये प्रयासों में कौनसा कथन असत्य है ?

- जून 2020 में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरुप्रयोग करने वाले श्री रवि प्रकाश मेहरडा, आईपीएस के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग।
- गृहमंत्री भारत सरकार को जून 2020 में ज्ञापन देकर श्री रविप्रकाश मेहरडा को बर्खास्त करने की मांग।
- राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके उक्त अतिरिक्त परिपत्र को निरस्त करने तथा श्री रवि प्रकाश मेहरडा को दण्डित करने की मांग।
- केन्द्रीय डीओपी तथा राजस्थान की एससी में ज्ञापन देकर श्री रविप्रकाश मेहरडा को दण्डित करने की मांग।

48. किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अजा/अजजा कामियों को सामान्य पद पर पदोन्नति देना न्यायपालिका का अपमान है, कानून और संविधान का उल्लंघन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 167 के अधीन दंडनीय अपराध है। इस विषय पर अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री, राजस्थान को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में निम्न में से कौनसा आधार अंगत है ?

- आर.के. सत्यवाले के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.11.1997 (रोस्टर) के विरुद्ध है।
- राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं के.के. भटनगर कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4)a के अधीन पारिणामिक वरिष्ठता से इसकी अनुमति राज्य सरकार को है।
- राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.07.2017, संविधान के अनुच्छेद 16(4), के मनोरमा बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, इन्दिरासाहनी एवं एम.नागराज के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध है।

49. वर्ष 2020 में राजस्थान सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से एलडीसी की 1254 पदों पर ब्रेकलॉग का बत कर एससी एवं एसटी के असम्पन्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। इस भर्ती को रूकवाने के लिए समता आन्दोलन द्वारा जो प्रयास किये गये उनके सम्बन्ध में कौनसा कथन असत्य है ?

- श्री निरंजन आर्य (आई.ए.एस), श्री आर. वेकटेश्वर (आई.ए.एस), श्री बी. एल.जाटावत (अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड) को दंडित किये जाने का ज्ञापन मुख्य सतकता आयुक्त दिवशी को ज्ञापन प्रेषित।
- श्री निरंजन आर्य (आई.ए.एस), श्री आर. वेकटेश्वर (आई.ए.एस), श्री बी. एल.जाटावत (अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड) के विरुद्ध राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परियाद दर्ज करवाया।
- श्री निरंजन आर्य (आई.ए.एस), श्री आर. वेकटेश्वर (आई.ए.एस), श्री बी. एल.जाटावत (अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड) को दण्डित करवाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को व्यक्तिगतः मिलकर ज्ञापन।
- भर्ती को निरस्त करवाने तथा श्री निरंजन आर्य (आई.ए.एस), श्री आर. वेकटेश्वर (आई.ए.एस), श्री बी.एल.जाटावत (अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड) को दण्डित करवाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर।

50. कोविड-19 महामारी की रोकथाम और उपचार के लिए केन्द्र सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल का सारांश एक पृष्ठ के पैम्पलेट "आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भाग्यइये" समता आन्दोलन द्वारा जारी किया गया। इस फ़र्म में कौनसा कथन असत्य है ?

- इस पैम्पलेट का विमोचन महामहिम राज्यपाल के कारकमलों से हमारे संरक्षक जस्टिस पानादेव जैन एवं प्रो. वैद्य बनवारी लाल गौड़ द्वारा करवाया गया।
- इस पैम्पलेट में कोविड-19 से बचाव, उपचार और टीका होने के बाद की सभी आयुर्वेदिक औषधियों को दिया गया है जो वेहद उपयोगी सिद्ध हो रहा है।
- इस पैम्पलेट के देवछापी प्रचार प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली को 5 सुझावों सहित ज्ञापन दिसम्बर 2020 में भेजा गया।
- समता आन्दोलन द्वारा अपने स्तर पर उक्त पैम्पलेट को छपवाकर राजस्थान के प्रत्येक जिलों में 10-10 हजार प्रतियाँ बटवाई गई है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय स्वर्ण।